

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं**. 1642] No. 1642] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2016/आषाढ़ 10, 1938 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2016/ASADHA 10, 1938

#### विदेश मंत्रालय

## आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 2016

का.आ. 2271(अ).—संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् ने अपनी 6774वीं बैठक में संकल्प 2048 (2012) (जो इस आदेश से उपाबंध 1 के रूप में संलग्न है), संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अधीन अंगीकार किया है, जो सभी राज्यों से उनके राज्यक्षेत्रों में संकल्प, 2048 (2012) के उपाबंध में सूचीबद्ध या संकल्प के अधीन स्थापित समिति द्वारा अभिहित व्यष्टियों के प्रवेश या अभिवहन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की अपेक्षा करता है।

और, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2048 (2012) में अंतर्विष्ट उपबंधों को सभी राज्यों में पूरी तरह कार्यान्वित करने की अपेक्षा करता है।

और, केंद्रीय सरकार ने गिनी बिसाऊ की एकता, संप्रभुता, स्वतंत्रता और राज्यक्षेत्र अखंडता के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के अध्याय 7 के अंतर्गत अंगीकृत सुरक्षा परिषद के उक्त संकल्पों को क्रियान्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के अधीन एक आदेश जारी करना अनिवार्य और सम्यक पाया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के अनुच्छेद 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है:---

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः** (1) उक्त आदेश का संक्षिप्त नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गिनी बिसाऊ संबंधी संकल्पों का क्रियान्वयन आदेश, 2016 है।
  - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- 2. परिभाषाः (1) इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
  - (क) "संकल्प" से 18 मई, 2012 को अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 2048 का 2012 अभिप्रेत है;
  - (ख) "सिमिति" से संकल्प 2048 का 2012 के पैरा 9 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा गठित सिमिति अभिप्रेत है।

3291 GI/2016 (1)

- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इस आदेश में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उनके उस विधि में है।
  - 3. **आदेश का व्यष्टियों और अस्तित्वों पर लागू होनाः** इस आदेश के समय-समय पर यथासंशोधित उपबंध ऐसे व्यष्टियों और अस्तित्वों को लागू होंगे जो इस आदेश से उपाबद्ध 1 में सूचीबद्ध है और जिसके अंतर्गत समिति द्वारा, समय-समय पर, पदाभिहित व्यष्टि और अस्तित्व है और जो उनकी वेबसाइट <a href="http://www.un.orcr/sc/committees/2048.htm">http://www.un.orcr/sc/committees/2048.htm</a> पर विनिर्दिष्ट और अद्यतन किए जाएं।
  - 4. **केंद्रीय सरकार के संकल्प को प्रभावी करने की शक्तियां** केन्द्रीय सरकार को संकल्प 2048 का (2012) से उपाबद्ध सूचीबद्ध या संकल्प के अधीन स्थापित समिति द्वारा अभिहित व्यष्टियों या अस्तित्वों को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की सभी शक्तियां होंगीः

परंतु यह प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा-

- (i) जहां समिति मामला दर मामला अवधारण करती है कि ऐसी यात्रा, जिसके अंतर्गत धार्मिक आबंध भी हैं, मानवीय जरूरत के आधार पर न्यायसंगत है।
- (ii) जहां ऐसा प्रवेश या अभिवहन न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ति के लिए आवश्यक है।
- (iii) जहां समिति मामला दर मामला अवधारण करती है कि छूट गिनी बिसाऊ में राष्ट्रीय सामंजस्य और शांति के उद्देश्यों को और आगे बढ़ाएगी तथा राज्यक्षेत्र में स्थायित्व लाएगी।

## अनुबंध ।

## [देखें अनुच्छेद 2(क)]

## प्रस्ताव 2048 (2012)

# 18 मई 2012 को अपनी 6774 वीं बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाई गई

सुरक्षा परिषद,

गिनी-बिसाऊ में स्थिति पर 21 अप्रैल 2012 एससी/पीआरएसटी/2012/15में सुरक्षा अध्यक्ष के वक्तव्य और 12 अप्रैल और 8 मई की प्रेस वक्तव्य का स्मरण करते हुए,

सैन्य नेतृत्व द्वारा 12 अप्रैल को सैन्य तख्तापलट पर अपनी निंदा को दोहराते हैं, जिसे गिनी-बिसाऊ में लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया के समापन पर कम आंका गया और जिसकी स्थापना "सैन्य कमान" के अपराधियों द्वारा तख्तापलट करके की गई.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा सैन्य तख्तापलट का सर्वसम्मित से निंदा का स्मरण करते हुएअफ्रीकी संघ (एयू), पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (इकोवास), पुर्तगाली बोलने वाले देशों के समुदाय (सीपीएलपी), यूरोपीय संघ (ईयू) और शांति स्थापना आयोग (पीबीसी) सहित,

मौजूदा संकट और हाल ही में सैन्य तख्तापलट के जवाब में इकोवास के नेतृत्व में मध्यस्थता प्रयासों के जवाब मेंए.यू., इकोवास, सीपीएलपीऔर यूरोपीय संघ के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए,

गिनी-बिसाऊ की राजनीतिक, सुरक्षा और विकास की चुनौतियों से निपटने हेतु समर्थन करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने और स्थिरीकरण के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करने के क्रम में अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के बीच सक्रिय और घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित करना,

मौजूदा संकट पर सुरक्षा परिषद की प्रतिक्रिया के लिए गिनी-बिसाऊ की सरकार द्वारा कॉल का संज्ञान लेते हुए,

अंतरिम राष्ट्रपति रायमुन्डोंपरेरा, प्रधानमंत्री कार्लोस गोम्स जूनियर और अन्य हिरासत में लिए गये अधिकारियों की रिहाई पर गौर करते हुए, संवैधानिक आदेश के तत्काल बहाली, गिनी-बिसाऊ के वैध लोकतांत्रिक सरकार की बहाली और चुनावी प्रक्रिया सैन्य तख्तापलट से बाधित सुविधाओं की बहाली के लिए "सैन्य कमांड" के इनकार की निंदा करने के संबंध में परिषद की मांगों को पुरा करने के लिए,

लूटपाट सिहत राज्य संपत्ति, मानव अधिकारों के उल्लंघन और गाली के मामलों की रिपोर्ट सिहत मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गये नागरिकों, नजरबंदी के दौरान बीमारों के उपचार,शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दमन और आंदोलन की स्वतंत्रता पर कई नागरिकों पर "सैन्य कमान" द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर, जैसा की गिनी-बिसाऊ में स्थिति (एस/2012/280) पर महासचिव की विशेष रिपोर्ट में बताया गया है,और रेखांकित किया गया है कि इस तरह के उल्लंघन और हनन के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, पर अपनी चिंता जताते हुए,

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा सहित और हिंसा को रोकने की जरूरत पर बल देते हुएसभी कृत्यों की निंदा ने इसकी पृष्टि की है,

यह तख्तापलट की वजह से मानवीय स्थिति और देश में आर्थिक गितविधियों पर इसके नकारात्मक प्रभाव को देखते हुएगहरी चिंता के साथ, गिनी बिसाउ/इकोवास/सीपीएलपीरोडमैप में परिकल्पित और गिनी-बिसाऊ में पुलिस बलों की जिम्मेदारी को रेखांकित किए गये राज्य संस्थाओं और नागरिक आबादी की रक्षा के लिए गिनी-बिसाऊ में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में,सुरक्षा बलों पर प्रभावी और जिम्मेदार नागरिक नियंत्रण सहितसुरक्षा क्षेत्र में सुधार के कार्यान्वयन के महत्व पर जोर देते हुए,

गिनी बिसाउ में राजनीतिक प्रक्रिया में सैन्य नेतृत्व के बारम्बार अवैध हस्तक्षेप की निंदा और चिंता व्यक्त करते हुए राजनीति में सेना के हस्तक्षेप और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के प्रभाव और गिनी-बिसाऊ में संगठित अपराध अधिक है, जिसने कानून और सुशासन न स्थापित करने और दण्ड मुक्ति और भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है,

अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नकारात्मक प्रभावों और गिनी-बिसाऊ और उप क्षेत्र संगठित अपराध पर गंभीर चिंता जताते हुए,

सैन्य तख्तापलट के परिणाम स्वरुप अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संभावित वृद्धि पर गहरी चिंता जताते हुए,

रेखांकित करते हुए कि, गिनी-बिसाऊ में अस्थिरता के लिए किसी भी स्थायी समाधानदण्ड मुक्ति से लड़ने के लिए ठोस कार्रवाई को शामिल करना चाहिएऔर यह सुनिश्चित करना चाहिए की राजनीति से प्रेरित हत्या और अन्य गंभीर अपराधों जैसे - अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित गतिविधियों और संवैधानिक आदेश के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के लिए लाया जाए,

इसके अलावा गिनी-बिसाऊ में स्थिर सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए स्थिरता और सुशासन के महत्व को रेखांकित करते हुए,

गिनी-बिसाऊ की संप्रभुता, स्थिरता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की जरूरत की पुष्टि,

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अनुच्छेद 41 के तहत कार्रवाई करते हुए,

- 1. मांग है कि सैन्य कमान को सभी सैनिकों को बैरकों में लौटनेऔर "सैन्य कमान" के सदस्यों के अधिकार से पदों पर त्यागने के द्वारायह सुनिश्चित करना किलोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया सहितसंविधान आदेश की बहाली और सम्मान के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए;
- 2. सभी राष्ट्रीय हितधारकों और गिनी-बिसाऊ के अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारों के लिए जरूरत पर संवैधानिक व्यवस्था की बहाली के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए जोर दिया, जैसा की ऊपर पैरा 1, और इस संदर्भ में

पुष्टि की गयी है, संवैधानिक व्यवस्था की बहाली के उद्देश्य से अपने मध्यस्थता प्रयास तथा संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ और सीपीएलपीके साथ घनिष्ठ समन्वय में जारी रखने के लिएइकोवास को प्रोत्साहित करती है;

3. अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय में भागीदारों के संबंधित पदों के अनुरूप करने के क्रम में महासचिव से सिक्रय रूप से इस प्रक्रिया में जुड़ने का अनुरोध किया जाना है, विशेष रूप से ए.यू., इकोवास, सीपीएलपी और यूरोपीय संघ के लिए, और सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को लागू करने, दवा की तस्करी का मुकाबला करने और दण्ड मुक्ति से लड़ने के उद्देश्य से ठोस उपायों के साथ एक व्यापक एकीकृत रणनीति विकसित करने के उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के अधिकतम समन्वय और पूरकता को सुनिश्चित करने के लिए;

## यात्रा पर प्रतिबंध

- 4. फैसला किया गया है कि सभी सदस्य राज्यों में प्रवेश या इस प्रस्ताव के अनुबंध में सूचीबद्ध व्यक्तियों के उनके क्षेत्रों के माध्यम से पारगमन या पैरा 9 के अनुसार स्थापित समिति द्वारा नामित व्यक्तियों या संस्थाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे, बशर्ते कि इस पैरा में कुछ अपने क्षेत्र में अपने स्वयं के नागरिकों प्रवेश मना करने के लिए एक राज्य भी उपकृत होगा;
- 5. फैसला किया गया है कि ऊपर पैरा 4 द्वारा लगाए गए उपायों लागू नहीं होगा:
  - (क) जहां समिति मामले के आधार पर निर्धारित करती हैिक ऐसी यात्रा धार्मिक दायित्व सहित मानवीय जरूरत के आधार पर जायज़ है;
  - (ख) जहां प्रवेश या पारगमन एक न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ति के लिए आवश्यक है;
  - (ग) जहां समिति मामलें के आधार पर निर्धारित करती है की छूट से शांति के उद्देश्यों को लाभ होगा और गिनी-बिसाऊ में राष्ट्रीय सुलहऔर इस क्षेत्र में स्थिरता आएगी।

## नियुक्ति मानदंड

- 6. फैसला किया गया है कि अनुच्छेद 4 में निहित उपाय अनुच्छेद 9 के अनुसार (ख) समिति द्वारा नामित व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगी:
  - (क) गिनी-बिसाऊ में स्थिरता को नजरअंदाज कर संवैधानिक व्यवस्था की बहाली को रोकने की मांग या कार्रवाई करने वाले विशेष रूप से वो जिन्होंने12 अप्रैल 2012 के तख्तापलट में एक प्रमुख भूमिका निभाई है और जिनका लक्ष्य अपने कार्यों के माध्यम सेकानून के शासन को कम से कम करना, नागरिकों की शक्ति को कम करना और देश में दण्ड मुक्ति और अस्थिरता को आगे बढ़ाना;
  - (ख) कार्रवाई के लिए या की ओर से या उस दिशा में या अन्यथा समर्थन या वित्तपोषण व्यक्तियों उप अनुच्छेद(क) में चिन्हित;
- 7. ध्यान दें कि इसमें समर्थन या वित्तपोषण के साधन शामिल हैं, लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं है, इसमें संगठित अपराध से प्राप्त आय, अवैध खेती, उत्पादन और नशीली दवाओं की तस्करी सहितऔर उनके पूर्ववर्ती में उद्भव और गिनी-बिसाऊ के माध्यम से यात्रा करना भी शामिल है;
- 8. सदस्य राज्यों को सिमिति के पास व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो ऊपर वर्णित अनुच्छेद 6 को मानदंडों के तहत आते हैं;

## नई प्रतिबंध समिति

9. सुरक्षा परिषद के एख समिति के सभी सदस्यों से मिलकर नियम प्रक्रिया के अपने अनंतिम नियम 28 के अनुसार एक नई समिति स्थापित करने का फैसला किया गया है,

परिषद (इस के साथ-साथ "सिमति"), निम्न कार्यों को शुरू करने के लिए:

- (क) अनुच्छेद 4 में लगाए गए उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए;
- (ख) अनुच्छेद 4 द्वारा लगाए गए उपायों को व्यक्ति विषय को नामित करने के लिए और ऊपर उल्लेखित अनुच्छेद 5 के अनुसार छूट के अनुरोध पर विचार करने के लिए;
- (ग) इस तरह के दिशा-निर्देशों की स्थापना के लिए जो ऊपर लगाए गए उपायों के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए आवश्यक हो सकते हैं;
- (घ) पहली रिपोर्ट हेतु अपने काम पर सुरक्षा परिषद को तीस दिनों के भीतर रिपोर्ट करने के लिए और उसके बाद सिमिति द्वारा आवश्यकता के अनुसार रिपोर्ट करने के लिए;
- (ङ) सिमिति और रुचि वाले सदस्य राज्यों और अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठनों विशेष रूप सेउन क्षेत्रों के लोगों के लिए राज्यों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके या संगठनों को सिमिति उपायों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने को प्रोत्साहित करने के लिए;
- (च) सभी राज्यों और अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठनों से तलाश करने के लिए जो कुछ भी जानकारी कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने और ऊपर उल्लेखित उपायों पर विचार कर सकते हैं;
- (छ) जांच करने और कथित उल्लंघन या इस प्रस्ताव में निहित उपायों के गैर-अनुपालन के संबंध में सूचना के आधार पर उचित कार्रवाई करने के लिए;
- 10. अनुच्छेद 4 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उनके द्वारा उठाए गये कदम के संबंध में सभी सदस्य राज्यों को इस प्रस्ताव के अपनाने के 120 दिनों के भीतर समिति को रिपोर्ट करने के लिए;
- 11. महासचिव इस प्रस्ताव के अपनाने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त अनुच्छेद 1 के कार्यान्वयन पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट परिषद को प्रस्तुत करने और अपने सभी तत्वों के कार्यान्वयन पर, साथ ही गिनी-बिसाऊ में मानवीय स्थिति पर;हर 90 दिनों के बाद नियमित रूप से रिपोर्ट परिषद को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करता है;

## प्रतिबद्धता की समीक्षा करने के लिए

- 12. पृष्टि की है कि गिनी-बिसाऊ में स्थिति को निरंतर समीक्षा के तहत रखना होगाऔर इस प्रस्ताव में निहित उपायों के औचित्य की समीक्षा करने के लिए इसे तैयार किया जाएगा,अतिरिक्त उपायों जैसे हथियार और वित्तीय उपायों पर एक प्रतिबंध, संशोधन, निलंबन या उपायों का फायदा उठाने, देश में के स्थिरीकरण की प्रगति में किसी भी समय पड़ने वाली जरूरत को ध्यान में रखते हुए, संवैधानिक व्यवस्था की बहाली, इस प्रस्ताव के अनुपालन के माध्यम से मजबूत बनाने सहित;
- 13. इस मामले के लिए सक्रिय रूप से जुड़े रहने का फैसला किया गया है।

#### अनुबद्ध

## यात्रा पर प्रतिबंध

1. जनरल एंटोनियो इनजैय(ए. के.ए.एंटोनियो इनजैय)

राष्ट्रीयता: गिनी बिसाऊ

जन्म की तारीख: 20 जनवरी 1955

जन्म स्थान: इंचेइया, सेक्टर डी बिसोरा, पूर्वोत्तर डी ओईयो, गिनी-बिसाऊ

माता-पिता: वसनाइनजैयऔर क्यूरीटचे कोफटे

आधिकारिक कार्य: लेफ्टिनेंट जनरल - सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ

पासपोर्ट: राजनयिक पासपोर्ट AA/000435

जारी होने की तिथिः 18.02.2010 जारी होन का स्थानः गिनी-बिसाऊ

समाप्ति तिथि: 18.02.2013

एंटोनियो व्यक्तिगत रूप से योजना बनाने और सैन्य-विद्रोह में अग्रणी रुप से शामिल था।

1.अप्रैल 2010 को प्रधानमंत्री, कार्लो कोम्स जूनियर और फिर सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, जोस ज़मोरा इंनडुटा की अवैध गिरफ्तारीके साथ; 2012 की चुनावी अविध के दौरानसशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपनी क्षमता में इनजैय ने निर्वाचित अधिकारियों को उखाड़ फेंकने और चुनावी प्रक्रिया का अंत करने करने की धमकी भरा बयान दिया है; एंटोनियो इनजैल 12 अप्रैल 2012 के तख्तापलट की योजना बनाने में शामिल है। तख्तापलट के बाद, "सैन्य कमान" द्वारा पहली विज्ञप्ति सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ द्वारा जारी किया गया था, जिसका नेतृत्व जनरल एंटोनियो ने किया था।

2.मेजर जनरल ममाडू टूरे (ए.के.ए.एन करुमाह)

राष्ट्रीयता: गिनी-बिसाऊ

जन्म की तारीख: 26 अप्रैल 1947

आधिकारिक कार्य: सशस्त्र बलों के स्टाफ के उप-प्रमुख

पासपोर्ट: राजनयिक पासपोर्ट DA0002186

जारी होने की तिथि: 30.03.2007

जारी होने का स्थान: गिनी-बिसाऊ

समाप्ति तिथि: 26.08.2013

"सैन्य कमान" के सदस्य, जो 12 अप्रैल 2012 के तख्तापलट के लिए स्वीकृत तौर पर जिम्मेदार हैं।

3. जनरल इस्टेवावो एनएमेना

राष्ट्रीयता: गिनी-बिसाऊ

जन्म की तारीख: 07 मार्च 1956

आधिकारिक कार्य: सशस्त्र बलों के महानिरीक्षक

"सैन्य कमान" के सदस्य, जो 12 अप्रैल 2012 के तख्तापलट के लिए स्वीकृत तौर पर जिम्मेदार हैं।

[भाग II-खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

4.ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम कामारा (ए.के.ए. "पापा कमारा")

राष्ट्रीयता: गिनी-बिसाऊ

जन्म की तारीख: 11 मई 1964

माता-पिता: सैरेबा कमारा और सेल क्वेटा

आधिकारिक कार्य: वायु सेना के चीफ ऑफ स्टाफ

पासपोर्ट: राजनयिक पासपोर्ट AAID00437

जारी होन की तिथि: 18.02.2010

जारी होने का स्थान: गिनी-बिसाऊ

समाप्ति तिथि: 18.02.2013

"सैन्य कमान" के सदस्य, जो 12 अप्रैल 2012 के तख्तापलट के लिए स्वीकृत तौर पर जिम्मेदार हैं।

5.लेफ्टिनेंट कर्नल डाबा नौलाना (ए.के.ए. डाबा ना वालना)

राष्ट्रीयता: गिनी-बिसाऊ

जन्म की तारीख: 6 जून 1966

माता-पिता: सांबा नौसेनाऔर इन-यूरिन नफाफे

आधिकारिक कार्य: "सैन्य कमान" के प्रवक्ता

पासपोर्ट: पासपोर्टSA000417

जारी होने की तिथि: 29.10.2003

जारी होने का स्थान: गिनी-बिसाऊ

समाप्ति तिथि: 10.03.2013

"सैन्य कमान" के प्रवक्ता, जो 12 अप्रैल 2012 के तख्तापलट के लिए स्वीकृत तौर पर जिम्मेदार हैं।

## अनुबंध ॥

# [देखें अनुच्छेद 3]

# 2048 (2012) समिति द्वारा प्रमाणित और संरक्षित सूची

सूची की संरचना

सूची में नीचे निर्दिष्ट दो वर्ग हैं:

## क. व्यक्तिगत

# ख. संस्थाओं और अन्य समूहों

असूचीयन के बारे में जानकारी को समिति की वेबसाइट <a href="http://www.un.org/scCommitteesdfp.shtml">http://www.un.org/scCommitteesdfp.shtml</a> से प्राप्त किया जा सकता है:

## क. व्यक्तिगत

जीबीआई.001 नाम: 1: इब्राइमा 2: (अमारा 3: 4: उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: क) ब्रिगेडियर जनरल ख) वायु सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जन्म तिथि: 11 मई 1964 पीओबी: उपलब्ध नहीं, अच्छा आचरण ए.के.ए.: पापा कैमरा खराब आचरण, ए.के.ए.: उपलब्ध नहीं, राष्ट्रीयता: गिनी-बिसाऊ, पासपोर्ट संख्या: AA|000437, 18 फरवरी 2010 को गिनी-बिसाऊ में जारी,(समाप्ति तिथि 18 फरवरी 2013) राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,पता: उपलब्ध नहीं,सूचीबद्ध: 18 मई 2012, अन्य सूचना: कमारा को प्रस्ताव 2048(2012) के अनुच्छेद संख्या 4 के अनुसार "सैन्य कमान के सदस्य" के रुप में18 मई 2012 सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने 12 अप्रैल, 2012 के तख्तापलट के लिए अपनी जिम्मेदारी को मान लिया है। उनके माता-पिता का नाम सैरेबा कमारा और सेल क्वेटा है।

जीबीआई.002 नामः 1ः सान्हा 2ः क्लूसे 3ः 4ः उपनामः पदनामः क) कैप्टन (नौ-सेना) ख) कार्यवाहक नौसेनाचीफ ऑफ स्टाफ जन्म-तिथिः 28 सितंबर 1965 पीओबीः उपलब्ध नहीं,अच्छी गुणवत्ता ए.के.ए.ः उपलब्ध नहीं, खराब गुणवत्ता ए.के.ए.ः उपलब्ध नहीं, राष्ट्रीयताः गिनी-बिसाऊ,पासपोर्ट संख्याः SA0O00515, 8 दिसम्बर 2003 कोगिनी-बिसाऊ में जारी (समाप्ति तिथि 29 अगस्त 2013) राष्ट्रीय पहचान संख्याः उपलब्ध नहीं,पताः उपलब्ध नहीं,सूचीबद्धः 18जुलाई 2012,अन्य सूचनाः क्लूसेको प्रस्ताव 2048(2012) के अनुच्छेद संख्या 4 के अनुसार "सैन्य कमान के सदस्य" के रुप में 18 मई 2012सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने 12 अप्रैल, 2012के तख्तापलट के लिए अपनी जिम्मेदारी को मान लिया है। जो एंटोनियो इनजैयके बहुत करीब थें। सान्हाक्लूसे ने एकीकृत "सैन्य कमान" प्रतिनिधिमंडल से26अप्रैल 2012 को आबिदजान में इकोवास के साथ मुलाकात की। उनके माता-पिता का नाम क्लूसे मुटचा और डालू इंमबुंगे है।

जीबीआई.003 नाम: 1: चरान्हा 2: डान्फा 3: 4: उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: क) कर्नल ख) सशस्त्र बलों के संयुक्त स्टाफ के संचालन के प्रमुख, जन्म-तिथि: 5 मार्च 1957,पीओबी: उपलब्ध नहीं, अच्छी गुणवत्ता ए.के.ए.: उपलब्ध नहीं, खराब गुणवत्ता ए.के.ए.: उपलब्ध नहीं, राष्ट्रीयता: गिनी-बिसाऊ,पासपोर्ट संख्या: AAIN29392, 29 सितम्बर 2011 को गिनी-बिसाऊ में जारी (समाप्ति तिथि 29 सितम्बर 2016) राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,पता: उपलब्ध नहीं,सूचीबद्ध: 18 जुलाई 2012 अन्य सूचना: डान्फाको प्रस्ताव 2048 (2012) के अनुच्छेद संख्या 4 के अनुसार "सैन्य कमान के सदस्य" के रुप में 18 मई 2012 सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने 12 अप्रैल, 2012 के तख्तापलट के लिए अपनी जिम्मेदारी को मान लिया है। चरान्हा सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ एंटोनियो इनजैय के करीबी सलाहकार थे।

जीबीआई.004 नाम: 1: इडरीसा 2: डजालो 3: 4: उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: क) मेजर ख) सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के प्रोटोकॉल सलाहकार ग) कर्नल घ) सशस्त्र बलों मुख्यालय के प्रोटोकॉल चीफ (बाद में) जन्म-तिथि: 18 दिसम्बर 1954 पीओबी: उपलब्ध नहीं,अच्छी गुणवत्ता ए.के.ए.: इडरीसा डजालो खराब गुणवत्ता ए.के.ए.: उपलब्ध नहीं, राष्ट्रीयता: गिनी-बिसाऊ, पासपोर्ट संख्या: AA|5040158, 12 अक्टूबर 2012 कोगिनी-बिसाऊ में जारी (समाप्ति तिथि2 अक्टूबर 2015) राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,पता: उपलब्ध नहीं, सूचीबद्ध:18 जुलाई 2012, अन्य सूचना: डजालोको प्रस्ताव 2048 (2012) के अनुच्छेद संख्या 4 के अनुसार "सैन्य कमान के सम्पर्क सूत्र" के रुप में 18 मई 2012 सूचीबद्ध किया गया,जिन्होंने 12 अप्रैल, 2012 के तख्तापलट के लिए अपनी जिम्मेदारी को मान लिया है और यह बहुत की सक्रिय सदस्य थे। ये पहले ऐसे अधिकारी थे जो सार्वजनिक रूप से "सैन्य कमांड" के लिए अपने संबद्धता स्वीकृत करने गया था और अपनी पहली विज्ञप्तियों (एन95, दिनांक 13 अप्रैल 2012) पर हस्ताक्षर किए। मेजर डजालोभी सैन्य खुफिया के अंतर्गत आता है।

जीबीआई.005 नाम: 1: एंटोनियो 2: इनजैय3: 4: उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: क) लेफ्टिनेंट जनरलख) सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, जन्म-तिथि: 20 जनवरी 1955, पीओबी: इंचेइया, सेक्टर डी बिसोरा, पूर्वोत्तर डी ओईयो, गिनी-बिसाऊ, अच्छी गुणवत्ता ए.के.ए.:एंटोनियो इनजैय खराब गुणवत्ता ए.के.ए.: उपलब्ध नहीं, राष्ट्रीयता: गिनी-बिसाऊ,पासपोर्ट संख्या: AA/000435,18 फरवरी 2010 को गिनी-बिसाऊ में जारी (समाप्ति तिथि 18 फरवरी 2013) राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं, पता: उपलब्ध नहीं, सूचीबद्ध: 18 मई 2012,अन्य सूचना:इनजैय को प्रस्ताव 2048 (2012) के अनुच्छेद संख्या 4 के अनुसार"एंटोनियो 1 अप्रैल 2010को प्रधानमंत्री, कार्लो कोम्स जूनियर और फिर सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ,

जोस ज़मोरा इंनडुटा की अवैध गिरफ्तारी के साथ; 2012 की चुनावी अविध के दौरान सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपनी क्षमता में इनजैय ने निर्वाचित अधिकारियों को उखाड़ फेंकने और चुनावी प्रक्रिया का अंत करने करने की धमकी भरा बयान दिया है; एंटोनियो इनजैल12 अप्रैल 2012 के तख्तापलट की योजना बनाने में शामिल है। तख्तापलट के बाद, "सैन्य कमान" द्वारा पहली विज्ञप्ति सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ द्वारा जारी किया गया था, जिसका नेतृत्व जनरल एंटोनियो ने किया था।" के रुप में सूचिबद्ध किया गया। एंटोनियो के माता-पिता का नाम वसनाइनजैय और क्यूरीटचे कोफटे है।

जीबीआई.006 नाम: 1: टछीपा 2: ना बिडोन 3: 4: उपनाम: उपलब्ध नहीं,पदनाम: क) लेफ्टिनेंट कर्नल ख) हेड ऑफ इन्टेलिजन्स, जन्म-तिथि: 28 मई 1954 पीओबी: उपलब्ध नहीं,अच्छी गुणवत्ता ए.के.ए.: उपलब्ध नहीं,खराब गुणवत्ताए.के.ए.: उपलब्ध नहीं,राष्ट्रीयता: गिनी-बिसाऊ, पासपोर्ट संख्या: DA0001564, 30 नवंम्बर 2005 को गिनी-बिसाऊ में जारी (समाप्ति तिथि15 मई 2011) राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,पता: उपलब्ध नहीं,सूचिबद्ध: 18 जुलाई 2012 अन्य सूचना: ना बिडोनको प्रस्ताव 2048 (2012) के अनुच्छेद संख्या 4 के अनुसार "सैन्य कमान के सदस्य" के रुप में 18 मई 2012 सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने 12 अप्रैल, 2012 के तख्तापलट के लिए अपनी जिम्मेदारी को मान लिया है। माता-पिता: नाबिडोन

जीबीआई.007 नाम: 1: टछाम 2: ना मेन 3: 4: उपनाम: उपलब्ध नहीं,पदनाम: क) लेफ्टिनेंट कर्नलख) सशस्त्र बलों के सैन्य अस्पताल के प्रमुख जन्म-तिथि: 27 फरवरी 1953 पीओबी: उपलब्ध नहीं,अच्छी गुणवत्ता ए.के.ए.: उपलब्ध नहीं, खराब गुणवत्ता ए.के.ए.: नामेन राष्ट्रीयता: गिनी-बिसाऊ, पासपोर्ट संख्या: SA0002264, 24 जुलाई 2006 को गिनी-बिसाऊ में जारी (समाप्ति तिथि 23 जुलाई 2009) राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं, पता:उपलब्ध नहीं, सूचिबद्ध:18 जुलाई 2012 अन्य सूचना: ना मेन कोप्रस्ताव 2048 (2012) के अनुच्छेद संख्या 4 के अनुसार "सैन्य कमान के सदस्य और इसके अलावा सैन्य हाई कमान (बिसाउ गिनी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च पदानुक्रम) के सदस्य" के रुप में 18 मई 2012 सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने 12 अप्रैल, 2012 के तख्तापलट के लिए अपनी जिम्मेदारी को मान लिया है। माता-पिता का नाम बाईयूटे और नडजाडे ना नोअ है।

जीबीआई.008 नाम: 1: इसटोवो 2: ना मेना 3: 4: उपनाम: उपलब्ध नहीं,पदनाम: सशस्त्र बल के महानिरीक्षक, जन्म-तिथि: 7 मार्च 1956, पीओबी: उपलब्ध नहीं,अच्छी गुणवत्ता ए.के.ए.: उपलब्ध नहीं, खराब गुणवत्ता ए.के.ए.: उपलब्ध नहीं, राष्ट्रीयता: गिनी-बिसाऊ, पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,पता: उपलब्ध नहीं,सूचीबद्ध:18 मई 2012, अन्य सूचना: ना मेना को प्रस्ताव 2048 (2012) के अनुच्छेद संख्या 4 के अनुसार "सैन्य कमान के सदस्य" के रुप में 18 मई 2012 सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने 12 अप्रैल, 2012 के तख्तापलट के लिए अपनी जिम्मेदारी को मान लिया है।

जीबीआई.009 नाम: 1: डाबा 2: नौलाना 3: 4: उपनाम: उपलब्ध नहीं,पदनाम: क) लेफ्टिनेंट कर्नल ख) "सैन्य कमान" के प्रवक्ता, जन्म-तिथि: 6 जून 1966, पीओबी: उपलब्ध नहीं,अच्छी गुणवत्ता ए.के.ए.: डाबा ना वाला खराब गुणवत्ता ए.के.ए.: उपलब्ध नहीं,राष्ट्रीयता: गिनी-बिसाऊ, पासपोर्ट संख्या: SA000417, 29 अक्टूबर 2003 को गिनी-बिसाऊ में जारी (समाप्ति तिथि 10 मार्च 2013) राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,पता: उपलब्ध नहीं,सूचीबद्ध: 18 मई 2012 अन्य सूचना: नौलानाको प्रस्ताव 2048 (2012) के अनुच्छेद संख्या 4 के अनुसार "सैन्य कमान के प्रवक्ता" के रुप में 18 मई 2012 सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने 12 अप्रैल, 2012 के तख्तापलट के लिए अपनी जिम्मेदारी को मान लिया है। उनके पिता का नाम सांबा नौलाना और माता का नाम इंनसाउने नानफाफे है।

जीबीआई.010 नाम: 1: जुलिक्यू 2: नहाटे 3: 4: उपनाम:उपलब्ध नहीं,पदनाम: क) लेफ्टिनेंट कर्नलख) पैराटूपर्स रेजीमेंट के कमांडर, जन्म-तिथि: 28 सितम्बर 1965, पीओबी: उपलब्ध नहीं, अच्छी गुणवत्ता ए.के.ए.:उपलब्ध नहीं, खराब गुणवत्ता ए.के.ए.:उपलब्ध नहीं, राष्ट्रीयता: गिनी-बिसाऊ, पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं, राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं, पता: उपलब्ध नहीं, सूचीबद्ध: 18 जुलाई 2012, अन्य सूचना: नहाटे को प्रस्ताव 2048 (2012) के अनुच्छेद संख्या 4 के अनुसार "सैन्य कमान के प्रवक्ता" के रुप में 18 मई 2012 सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने 12 अप्रैल, 2012 के तख्तापलट के लिए अपनी

जिम्मेदारी को मान लिया है। नहाटे लेफ्टिनेंट कर्नल एंटोनियो इनजैय के एक वफादार सहयोगी थे जो 12 अप्रैल 2012 के तख्तापलट के लिए सैन्य अभियान हेतु सामग्री मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार है।

जीबीआई.011 नाम: 1: ममाडू 2: टूरे 3: 4: उपनाम: उपलब्ध नहीं,पदनाम: क) मेजर जनरलख) सशस्त्र बलों के स्टाफ के उप प्रमुख, जन्म-तिथि: 26 अप्रैल 1947, पीओबी: उपलब्ध नहीं,अच्छी गुणवत्ता ए.के.ए.: उपलब्ध नहीं, खराब गुणवत्ता ए.के.ए.: एन' करुमाह राष्ट्रीयता: गिनी-बिसाऊ, पासपोर्ट संख्या: DA0002186, 30 मार्च 2007 कोगिनी-बिसाऊ में जारी (समाप्ति तिथि 26 अगस्त 2013) राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,पता:उपलब्ध नहीं,सूचीबद्ध: 18 मई 2012 अन्य सूचना: टूरे को प्रस्ताव 2048 (2012) के अनुच्छेद संख्या 4 के अनुसार "सैन्य कमान के सदस्य" के रुप में 18 मई 2012 सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने 12 अप्रैल, 2012 के तख्तापलट के लिए अपनी जिम्मेदारी को मान लिया है।

[फ़ा. सं. यू. II/152/3/2016]

रुद्ररेन्द्र टंडन, संयुक्त सचिव [यू.एन.पी.]

# MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS ORDER

New Delhi, the 30th June, 2016

**S.O. 2271(E).**—Whereas the Security Council of the United Nations in its 6774<sup>th</sup> Meeting adopted Resolution 2048 (2012) [appended to this Order as Annexure 1], under Chapter VII of the Charter of the United Nations which required all States, to take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of individuals listed in the annexure of resolution 2048(2012) or designated by the Committee established under the resolution;

And whereas, Resolution 2048(2012) of the Security Council of the United Nations requires States to fully implement the provisions contained in it;

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to issue an Order under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to implement the said Resolution of the Security Council adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations to protect the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Guinea Bissau;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order to give effect to the said Resolution, namely:-

- **1. Short title and commencement .-** (1) This Order may be called the Implementation of the United Nations Security Council Resolution on Guinea-Bissau Order, 2016.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions** .- (1) In this Order, unless the context otherwise requires, -
  - (a) "Resolution" means the Resolution 2048(2012) adopted by the Security Council on 18<sup>th</sup> May, 2012;
  - (b) "Committee" means the Committee established by the Security Council of the United Nations in accordance with paragraph 9 of the Resolution 2048(2012).
  - (2) Words and expressions used but not defined in this Order and defined in any law for the time being in force shall have the meanings respectively assigned to them in such laws.
- **3. Application of Order to individuals and entities**. The provisions of this Order, as amended from time to time, apply to individual and entities listed in the annexure 2 and which include individuals and entities as designated by the Committee from time to time and updated and specified on their website: http://www.un.org/sc/committees/2048/2048.htm.

4. Powers of the Central Government to give effect to the Resolution - The Central Government shall have all the powers to take necessary measures to prevent the entry of individuals and entities into or transit through Indian territory of individuals or entities listed in the annex of resolution 2048(2012) or designated by the Committee established under the resolution:

Provided that the ban shall not apply –

- (i) where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation;
- (ii) where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial process;
- (iii) where the Committee determines on a case-by-case basis that an exemption would further the objectives of peace and national reconciliation in Guinea-Bissau and stability in the region.

#### **ANNEXURE 1**

[See paragraph 2(a)]

**Resolution 2048 (2012)** 

## Adopted by the Security Council at its 6774th meeting, on

## 18 May 2012

The Security Council,

Recalling the Statement of its President of 21 April 2012 (S/PRST/2012/15) and the press statements of 12 April and 8 May on the situation in Guinea-Bissau,

Reiterating its strong condemnation of the military coup on 12 April by the military leadership, which undermined the conclusion of the democratic electoral process in Guinea-Bissau, and of the establishment by the coup perpetrators of a "Military Command",

Recalling the unanimous condemnation of the military coup by the international community, including by the African Union (AU), the Economic Community of West African States (ECOWAS), the Community of Portuguese Speaking Countries (CPLP), the European Union (EU) and the Peacebuilding Commission (PBC),

Taking note of the efforts by the AU, ECOWAS, CPLP and the EU in response to the current crisis and the mediation efforts led by ECOWAS in response to the recent military coup,

Underlining the need for active and close coordination among international partners in Order to restore constitutional Order and develop a comprehensive strategy of stabilization to support Guinea-Bissau address its political, security and development challenges,

Taking note of the calls by the Government of Guinea-Bissau for a response of the Security Council to the current crisis,

Taking note of the release of interim President Raimundo Pereira, Prime Minister Carlos Gomes Júnior and other detained officials,

Deploring the continued refusal of the "Military Command" to heed the Council's demands, for the immediate restoration of the constitutional Order, the reinstatement of the legitimate democratic Government of Guinea-Bissau and the resumption of the electoral process interrupted by the military coup,

Expressing concern about reports of cases of looting, including of State assets, human rights violations and abuses, including arbitrary detentions, ill treatment during detention, the repression of peaceful demonstrations and the restrictions on the freedom of movement imposed by the "Military Command" on a number of individuals, as noted in the Special Report of the Secretary-General on the situation in Guinea-Bissau (S/2012/280), and underlining that those responsible for such violations and abuses must be held accountable,

Affirming its condemnation of all acts of violence, including against women and children, and stressing the need to prevent violence,

Noting with deep concern the worrying humanitarian situation caused by the coup d'état and its negative impact on the economic activity in the country,

Stressing the importance of Security Sector Reform implementation, including effective and responsible civilian control over the security forces, as a crucial element for long term stability in Guinea-Bissau, as envisaged in the Guinea Bissau/ECOWAS/CPLP Roadmap and underlining the responsibility of police forces in Guinea-Bissau to protect state institutions and the civilian population,

Deploring the recurrent illegal interference of the military leadership in the political process in Guinea-Bissau and expressing concern that interference of the military in politics and the impact of illicit drug trafficking and organized crime in Guinea-Bissau have significantly hampered efforts to establish rule of law and good governance and tackle impunity and corruption,

Expressing grave concern over the negative impacts of illicit drug trafficking and organized crime on Guinea-Bissau and the sub region,

Expressing deep concern about the possible increase in illicit drug trafficking as a result of the military coup,

Underlining that any lasting solution to instability in Guinea-Bissau should include concrete actions to fight impunity and ensure that those responsible for politically-motivated assassinations and other serious crimes such as illicit drug trafficking-related activities and breaches of constitutional Order are brought to justice,

Further underlining the importance of stability and good governance for durable social and economic development in Guinea-Bissau,

Reaffirming the need to uphold and respect the sovereignty, unity and territorial integrity of Guinea-Bissau,

Mindful of its primary responsibility for the maintenance of international peace and security under the Charter of the United Nations,

Acting under article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations,

- 1. Demands that the Military Command takes immediate steps to restore and respect constitutional Order, including a democratic electoral process, by ensuring that all soldiers return to the barracks, and that members of the "Military Command" relinquish their positions of authority;
- 2. Stresses the need for all national stakeholders and Guinea-Bissau's international bilateral and multilateral partners to remain committed to the restoration of constitutional Order, as affirmed in paragraph 1 above and, in this context, encourages ECOWAS to continue its mediation efforts aimed at the restoration of constitutional Order, in close coordination with the United Nations, the AU and CPLP;
- 3. Requests the Secretary-General to be actively engaged in this process, in Order to harmonize the respective positions of international bilateral and multilateral partners, particularly the AU, ECOWAS, CPLP and the EU, and ensure maximum coordination and complementarity of international efforts, with a view to developing a comprehensive integrated strategy with concrete measures aimed at implementing security sector reform, political and economic reforms, combating drug-trafficking and fighting impunity;

#### Travel ban

- 4. Decides that all Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of individuals listed in the annex of this resolution or designated by the Committee established pursuant to paragraph 9 below, provided that nothing inthis paragraph shall oblige a State to refuse its own nationals entry into its territory;
- 5. Decides that the measures imposed by paragraph 4 above shall not apply:
- (a) Where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation;
- (b) Where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial process;
- (c) Where the Committee determines on a case-by-case basis that an exemption would further the objectives of peace and national reconciliation in Guinea-Bissau and stability in the region;

## Designation criteria

6. Decides that the measures contained in paragraph 4 shall apply to the individuals designated by the Committee, pursuant to paragraph 9 (b):

- (a) Seeking to prevent the restoration of the constitutional Order or taking action that undermines stability in Guinea-Bissau, in particular those who played a leading role in the coup d'état of 12 April 2012 and who aim, through their actions, at undermining the rule of law, curtailing the primacy of civilian power and furthering impunity and instability in the country;
- (b) Acting for or on behalf of or at the direction of or otherwise supporting or financing individuals identified in subparagraph (a);
- 7. Notes that such means of support or financing include, but are not limited to, the proceeds from organized crime, including the illicit cultivation, production and trafficking of narcotic drugs and their precursors originating in and transiting through Guinea-Bissau;
- 8. Strongly encourages Member States to submit to the Committee names of individuals who meet the criteria set out in paragraph 6 above;

**New Sanctions Committee** 

9. Decides to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the

Council (herein "the Committee"), to undertake to following tasks:

- (a) To monitor implementation of the measures imposed in paragraph 4;
- (b) To designate those individuals subject to the measures imposed by paragraph 4 and to consider requests for exemptions in accordance with paragraph 5 above;
- (c) To establish such guidelines as may be necessary to facilitate the implementation of the measures imposed above;
- (d) To report within thirty days to the Security Council on its work for the first report and thereafter to report as deemed necessary by the Committee;
- (e) To encourage a dialogue between the Committee and interested Member States and international, regional and sub regional organizations, in particular those in the region, including by inviting representatives of such States or organizations to meet with the Committee to discuss implementation of the measures;
- (f) To seek from all States and international, regional and sub regional organizations whatever information it may consider useful regarding the actions taken by them to implement effectively the measures imposed above;
- (g) To examine and take appropriate action on information regarding alleged violations or non-compliance with the measures contained in this resolution:
- 10. Calls upon all Member States to report to the Committee within 120 days of the adoption of this resolution on the steps they have taken with a view to implementing effectively paragraph 4;
- 11. Requests the Secretary-General to submit to the Council an initial report on the implementation of paragraph 1 above within 15 days of the adoption of this resolution, and regular reports, every 90 days thereafter, on the implementation of all its elements, as well as on the humanitarian situation in Guinea-Bissau;

#### **Commitment to review**

- 12. Affirms that it shall keep the situation in Guinea-Bissau under continuous review and that it shall be prepared to review the appropriateness of the measures contained in this resolution, including the strengthening through additional measures, such as an embargo on arms and financial measures, modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at any time in light of the progress achieved in the stabilization of the country, the restoration of the constitutional Order, in compliance with this resolution;
- 13. Decides to remain actively seized of the matter.

#### Annex

#### **Travel Ban**

1. General António INJAI (a.k.a António INDJAI)

Nationality: Guinea-Bissau

Date of birth: 20 January 1955

Place of birth: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau

Parentage: Wasna Injai and Quiritche Cofte

Official function: Lieutenant General – Chief of Staff of the Armed Forces

Passport: Diplomatic passport AAID00435

Date of issue: 18.02.2010 Place of issue: Guinea-Bissau Date of expiry: 18.02.2013

António Injai was personally involved in planning and leading the mutiny of

1 April 2010, culminating with the illegal apprehension of the Prime Minister, Carlo Gomes Junior, and the then Chief of Staff of the Armed Forces, José Zamora Induta; during the 2012 electoral period, in his capacity as Chief of Staff of the Armed Forces, Injai made statements threatening to overthrow the elected authorities and to put an end to the electoral process; António Injai has been involved in the operational planning of the coup d'état of 12 April 2012. In the aftermath of the coup, the first communiqué by the "Military Command" was issued by the Armed Forces General Staff, which is led by General Injai.

2. Major General Mamadu TURE (a.k.a. N'KRUMAH)

Nationality: Guinea-Bissau Date of birth: 26 April 1947

Official function: Deputy Chief of Staff of the Armed Forces

Passport: Diplomatic passport DA0002186

Date of issue: 30.03.2007 Place of issue: Guinea-Bissau Date of expiry: 26.08.2013

Member of the "Military Command" which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012.

3. General Estêvão NA MENA

Nationality: Guinea-Bissau Date of birth: 07 March 1956

Official function: Inspector-General of the Armed Forces

Member of the "Military Command" which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012.

4. Brigadier General Ibraima CAMARÁ (a.k.a. "Papa Camará")

Nationality: Guinea-Bissau Date of birth: 11 May 1964

Parentage: Suareba Camará and Sale Queita Official function: Chief of Staff of the Air Force Passport: Diplomatic passport AAID00437

Date of issue: 18.02.2010 Place of issue: Guinea-Bissau Date of expiry: 18.02.2013

Member of the "Military Command" which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012.

## 5. Lieutenant colonel Daba NAUALNA (a.k.a. Daba Na Walna)

Nationality: Guinea-Bissau

Date of birth: 6 June 1966

Parentage: Samba Naualna and In-Uasne Nanfafe

Official function: Spokesperson of the "Military Command"

Passport: Passport SA000417
Date of issue: 29.10.2003
Place of issue: Guinea-Bissau

Date of expiry: 10.03.2013

Spokesperson of the "Military Command" which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April

2012.

#### **ANNEXURE 2**

## [See paragraph 3]

## The List established and maintained by the 2048 (2012) Committee

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

#### A. Individuals

## B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found on the Committee's website at: http://www.un.org/sc/Committees/dfp.shtml

## A. Individuals

**GBi.001** Name: 1: IBRAIMA 2: CAMARÁ 3: 4: Title: na Designation: a) Brigadier General b) Chief of Staff of the Air Force DOB: 11 May 1964 POB: na Good quality a.k.a.: Papa Camará Low quality a.k.a.: na Nationality: Guinea-Bissau Passport no: AAID00437, issued on 18 Feb. 2010, issued in Guinea-Bissau (Expiration date 18 Feb. 2013) National identification no: na Address: na Listed on: 18 May 2012 Other information: Camará was listed on 18 May 2012 pursuant to paragraph 4 of resolution 2048 (2012) as "Member of the "Military Command", which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012." Father's name is Suareba Camará; Mother's name is Sale Queita

**GBi.002** Name: 1: SANHA 2: CLUSSÉ 3: 4: Title: na Designation: a) Captain (Navy) b) Acting Navy Chief of Staff DOB: 28 Sep. 1965 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Guinea-Bissau Passport no: SA0000515, issued on 8 Dec. 2003, issued in Guinea-Bissau (Expiration date 29 Aug. 2013) National identification no: na Address: na Listed on: 18 Jul. 2012 Other information: Clussé was listed on 18 Jul. 2012 pursuant to paragraph 4 of resolution 2048 (2012) as "Member of the "Military Command" which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012. Very close to António Injai. Sanha Clussé integrated the "Military Command" delegation that met with ECOWAS in Abidjan on 26 April 2012." Father's name is Clusse Mutcha; Mother's name is Dalu Imbungue.

**GBi.003** Name: 1: CRANHA 2: DANFA 3: 4: Title: na Designation: a) Colonel b) Head of Operations of the Armed Forces Joint Staff DOB: 5 Mar. 1957 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Guinea-Bissau Passport no: AAIN29392, issued on 29 Sep. 2011, issued in Guinea-Bissau (Expiration date 29 Sep. 2016) National identification no: na Address: na Listed on: 18 Jul. 2012 Other information: Danfa was listed on 18 Jul. 2012 pursuant to paragraph 4 of resolution 2048 (2012) as "Member of the "Military Command" which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012. Close Advisor to Armed Forces Chief of Staff António Injai."

**GBi.004** Name: 1: IDRISSA 2: DJALÓ 3: 4: Title: na Designation: a) Major b) Protocol Advisor to the Armed Forces Chief of Staff c) Colonel d) Chief of Protocol of the Headquarters of the Armed Forces (subsequently) DOB: 18 Dec. 1954 POB: na Good quality a.k.a.: Idriça Djaló Low quality a.k.a.: na Nationality: Guinea-Bissau Passport no: AAISO40158, issued on 12 Oct. 2012, issued in Guinea-Bissau (Expiration date 2 Oct. 2015) National identification no: na Address: na Listed on: 18 Jul. 2012 Other information: Djaló was listed on 18 Jul. 2012 pursuant to paragraph 4 of resolution 2048 (2012) as "Point of Contact for the "Military Command" which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012 and one of its most active members. He was one of the first officers to publicly assume his affiliation to the "Military Command", having signed one of its first communiqués (n°5, dated 13 April 2012). Major Djaló also belongs to the Military Intelligence.

GBi.005 Name: 1: ANTÓNIO 2: INJAI 3: 4: Title: na Designation: a) Lieutenant General b) Chief of Staff of the Armed Forces DOB: 20 Jan. 1955 POB: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau Good quality a.k.a.: António Indjai Low quality a.k.a.: na Nationality: Guinea-Bissau Passport no: AAID00435, issued on 18 Feb. 2010, issued in Guinea-Bissau (Expiration date 18 Feb. 2013) National identification no: na Address: na Listed on: 18 May 2012 Other information: Injai was listed on 18 May 2012 pursuant to paragraph 4 of resolution 2048 (2012) as "António Injai was personally involved in planning and leading the mutiny of 1 April 2010, culminating with the illegal apprehension of the Prime Minister, Carlo Gomes Junior, and the then Chief of Staff of the Armed Forces, José Zamora Induta; during the 2012 electoral period, in his capacity as Chief of Staff of the Armed Forces, Injai made statements threatening to overthrow the elected authorities and to put an end to the electoral process; António Injai has been involved in the operational planning of the coup d'état of 12 April 2012. In the aftermath of the coup, the first communiqué by the "Military Command" was issued by the Armed Forces General Staff, which is led by General Injai." Father's name is Wasna Injai; Mother's name is Quiritche Cofte.

**GBi.006** Name: 1: TCHIPA 2: NA BIDON 3: 4: Title: na Designation: a) Lieutenant-colonel b) Head of Intelligence DOB: 28 May 1954 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Guinea-Bissau Passport no: DA0001564, issued on 30 Nov. 2005, issued in Guinea-Bissau (Expiration date 15 May 2011) National identification no: na Address: na Listed on: 18 Jul. 2012 Other information: Na Bidon was listed on 18 Jul. 2012 pursuant to paragraph 4 of resolution 2048 (2012) as "Member of the "Military Command" which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012." Parentage: "Nabidom

**GBi.007** Name: 1: TCHAM 2: NA MAN 3: 4: Title: na Designation: a) Lieutenant-colonel b) Head of the Armed Forces Military Hospital DOB: 27 Feb. 1953 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Namam Nationality: Guinea-Bissau Passport no: SA0002264, issued on 24 Jul. 2006, issued in Guinea-Bissau (Expiration date 23 Jul. 2009) National identification no: na Address: na Listed on: 18 Jul. 2012 Other information: Na Man was listed on 18 Jul. 2012 pursuant to paragraph 4 of resolution 2048 (2012) as "Member of the "Military Command" which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012. Also a member of the Military High Command (highest hierarchy of the BissauGuinean Armed Forces)." Father's name is Biute Naman; Mother's name is Ndjade Na Noa.

**GBi.008** Name: 1: ESTÊVÃO 2: NA MENA 3: 4: Title: na Designation: Inspector-General of the Armed Forces DOB: 7 Mar. 1956 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Guinea-Bissau Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 18 May 2012 Other information: Na Mena was listed on 18 May 2012 pursuant to paragraph 4 of resolution 2048 (2012) as "Member of the "Military Command" which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012."

**GBi.009** Name: 1: DABA 2: NAUALNA 3: 4: Title: na Designation: a) Lieutenant-colonel b) Spokesperson of the "Military Command" DOB: 6 Jun. 1966 POB: na Good quality a.k.a.: Daba Na Walna Low quality a.k.a.: na Nationality: Guinea-Bissau Passport no: SA000417, issued on 29 Oct. 2003, issued in Guinea-Bissau (Expiration date 10 Mar. 2013) National identification no: na Address: na Listed on: 18 May 2012 Other information: Naualna was listed on 18 May 2012 pursuant to paragraph 4 of resolution 2048 (2012) as "Spokesperson of the "Military Command" which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012." Father's name is Samba Naualna; Mother's name is InUasne Nanfafe.

**GBi.010** Name: 1: JÚLIO 2: NHATE 3: 4: Title: na Designation: a) Lieutenant-colonel b) Commander of the Paratroops Regiment DOB: 28 Sep. 1965 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Guinea-Bissau Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 18 Jul. 2012 Other information: Nhate was listed on 18 Jul. 2012 pursuant to paragraph 4 of resolution 2048 (2012) as "Member of the "Military Command" which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012. A loyal ally of António Injai, Lt.Col. Júlio Nhate has the material responsibility for the 12 April 2012 coup, having conducted the military operation."

**GBi.011** Name: 1: MAMADU 2: TURE 3: 4: Title: na Designation: a) Major General b) Deputy Chief of Staff of the Armed Forces DOB: 26 Apr. 1947 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: N'Krumah Nationality: Guinea-Bissau Passport no: DA0002186, issued on 30 Mar. 2007, issued in Guinea-Bissau (Expiration date 26 Aug. 2013) National identification no: na Address: na Listed on: 18 May 2012 Other information: Ture was listed on 18 May 2012 pursuant to paragraph 4 of resolution 2048 (2012) as "Member of the "Military Command" which has assumed responsibility for the coup d'état of 12 April 2012."

[F. No. U-II/152/3/2016]

RUDRENDRA TANDON, Jt. Secy. [UNP]